



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062020-220146
CG-DL-E-24062020-220146

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]
No. 311]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2020/आषाढ 3, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2020/ASADHA 3, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

सं. 49/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 402(अ).— केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) 2017 (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 जून, 2020 को उस तारीख के रूप में, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 118, 125, 129 और 130 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

[फा.सं. सीबीईसी- 20/06/09/2019- जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th June, 2020

No. 49/2020 –Central Tax

G.S.R. 402(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Finance Act, 2020 (12 of 2020) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the 30th day of June, 2020, as the date on which the provisions of sections 118, 125, 129 and 130 of the said Act, shall come into force.

[F. No. CBEC- 20/06/09/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

सं.-50/2020-केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 403(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवाकर (सातवाँ संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये 01 अप्रैल 2020 से प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 के नियम 7 में, तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“तालिका

क्रम संख्या	धारा जिसके तहत संयुक्त उधग्रहण का विकल्प चुना गया है	पंजीकृत व्यक्तियों का प्रवर्ग	कर की दर
(1)	(1 क)	(2)	(3)
1.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	ऐसे विनिर्माताओं से, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, भिन्न विनिर्माता	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कारोबार का आधा फीसदी
2.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियाँ करने वाला पूर्तिकार	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कारोबार का ढाई फीसदी
3.	धारा 10 की उपधारा (1) या (2)	धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के उपबंधों के अधीन संयुक्त उधग्रहण के लिए पात्र कोई अन्य पूर्तिकार	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में कर योग्य माल और सेवाओं की आपूर्तियों के कारोबार का आधा फीसदी

4.	धारा 10 की उपधारा (2 क)	पंजीकृत व्यक्ति जो धारा 10 की उपधारा (1) या (2) के तहत संयुक्त उधग्रहण के पात्र नहीं हैं, लेकिन धारा 10 के उप-धारा (2 ए) के तहत कर सदाय का चयन करने के लिए पात्र हैं।	राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में माल और सेवाओं की कर योग्य आपूर्तियों के कारोबार का तीन फीसदी।”।
----	-------------------------	---	---

[फा.सं.-सीबीईसी-20/06/09/2019-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 03/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किये गए और सा.का.नि. संख्या 394(अ), तारीख 19 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 48/2020-केन्द्रीय कर, तारीख 19 जून, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2020

No. 50/2020 – Central Tax

G.S.R. 403(E).—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

- (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Seventh Amendment) Rules, 2020.
- (2) They shall come into force with effect from the 01st day of April, 2020.
- In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, in rule 7, for the Table, the following Table shall be substituted, namely:-

“TABLE

Sl. No.	Section under which composition levy is opted	Category of registered persons	Rate of tax
(1)	(1A)	(2)	(3)
1.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Manufacturers, other than manufacturers of such goods as may be notified by the Government	half per cent. of the turnover in the State or Union territory
2.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Suppliers making supplies referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II	two and a half per cent. of the turnover in the State or Union territory
3.	Sub-sections (1) and (2) of section 10	Any other supplier eligible for composition levy under sub-sections (1) and (2) of section 10	half per cent. of the turnover of taxable supplies of goods and services in the State or Union territory
4.	Sub-section (2A) of section 10	Registered persons not eligible under the composition levy under sub-sections (1) and (2), but eligible to opt to pay tax under sub-section (2A), of section 10	three per cent. of the turnover of taxable supplies of goods and services in the State or Union territory.”.

[F. No. CBEC-20/06/09/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published vide number G.S.R. 610(E), dated the 19th June, 2017 and last amended vide notification No. 48/2020 - Central Tax, dated the 19th June, 2020 published vide number G.S.R. 394 (E), dated the 19th June, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

सं- 51/2020- केन्द्रीय कर

सा. का.नि. 404(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं०13/2017- केन्द्रीय कर, दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 661(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं, देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं:-

तालिका

क्र०सं० (1)	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	ब्याज की दर (3)	कर अवधि (4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद 24 जून, 2020 तक 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो और जिनका कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, गोवा राज्य, केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य, तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र, पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में है	30 जून, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत 3 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020 मार्च, 2020

		6 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	अप्रैल, 2020
		12 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	मई, 2020
		23 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	जून, 2020
		27 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	जुलाई, 2020
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो और जिनका कारबार का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश राज्य, पंजाब राज्य, उत्तराखंड राज्य, हरियाणा राज्य, राजस्थान राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, सिक्किम राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य, नागालैंड राज्य, मणिपुर राज्य, मिजोरम राज्य, त्रिपुरा राज्य, मेघालय राज्य, असम राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, झारखंड राज्य या ओडिशा राज्य, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में है	30 जून, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020
		5 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	मार्च, 2020
		9 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	अप्रैल, 2020
		15 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक	मई, 2020

		9 प्रतिशत	
		25 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	जून, 2020
		29 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	जुलाई, 2020 ¹

[फा.सं.-सीबीईसी-20/06/09/2019-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट: मूल अधिसूचना सं. 13/2017, दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 661 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और पश्चातवर्ती अधिसूचना सं. 31/2020-केंद्रीय कर, तारीख 3 अप्रैल, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 231(अ), तारीख 3 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अंतिम संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2020

No. 51/2020 – Central Tax

G.S.R. 404(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 148 of the said Act, the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.13/2017 – Central Tax, dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 661(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely :—

“Provided that the rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table given below for the period mentioned therein, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in **FORM GSTR-3B**, but fail to furnish the said return along with payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due date, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Rate of interest (3)	Tax period (4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	Nil for first 15 days from the due date, and 9 per cent thereafter till 24 th day of June, 2020	February, 2020, March 2020, April, 2020
2.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana or Andhra Pradesh or the Union territories of	Nil till the 30 th day of June, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	February, 2020

	Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep	Nil till the 3rd day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	March, 2020
		Nil till the 6th day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	April, 2020
		Nil till the 12th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	May, 2020
		Nil till the 23rd day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	June, 2020
		Nil till the 27th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	July, 2020
		Nil till the 30th day of September, 2020	
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the States of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha or the Union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh and Delhi	Nil till the 30th day of June, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	February, 2020
		Nil till the 5th day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	March, 2020
		Nil till the 9th day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	April, 2020
		Nil till the 15th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	May, 2020
		Nil till the 25th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	June, 2020
		Nil till the 29th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	July, 2020.?.
		Nil till the 30th day of September, 2020	

[F. No. CBEC-20/06/09/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification number 13/2017 – Central Tax, dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.661(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended vide notification number 31/2020 – Central Tax, dated the 3rd April, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.231(E), dated the 3rd April, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

सं. 52/ 2020- केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 405(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की शिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 76/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, जिसे सा.का.नि. 1253 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में,—

(i) तीसरे परंतुक में तालिका के स्थान पर निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“तालिका

क्र.सं.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का वर्ग	कर अवधि	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त करोड़ 5 रुपये तक हैं, जिनका मूल कारोबार का स्थान छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिल नाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्य में, या संघ शासित प्रदेश दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप एवं लक्षद्वीप है	फरवरी, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3 -ख में विवरणी 30 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3 -ख में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3 -ख में विवरणी 6 जुलाई, 2020या उससे जाती है पहले प्रस्तुत की
		मई, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3 -ख में विवरणी 12 सितंबर, 2020या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		जून, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3 -ख में विवरणी 23 सितंबर, 2020या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		जुलाई, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3 -ख में विवरणी 27 सितंबर, 2020या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

3	करदाता जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त करोड़ रुपये 5 तक हैं, जिनका मूल कारोबार का स्थान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड या उड़ीसा राज्य में, या संघ शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ या दिल्ली में है	फरवरी, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3 -ख में विवरणी 30 जून, 2020या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3 -ख में विवरणी 5 जुलाई, 2020या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3 -ख में विवरणी 9 जुलाई, 2020या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		मई, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3 -ख में विवरणी 15 सितंबर, 2020या उससे प्रस्तुत की जाती हैपहले प्र
		जून, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3 -ख में विवरणी 25 सितंबर, 2020या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		जुलाई, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3 -ख में विवरणी 29 सितंबर, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

(ii) तीसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुको को अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“ परंतु यह भी कि उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत किसी कर अवधि में देय विलंब शुल्क को रुपये दो सौ पचास से अधिक अधित्यजन करती है जिन्होंने नियत तारीख तक माह जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जुलाई, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं:

परंतु यह भी कि यदि उक्त विवरणी में संदेय केंद्रीय कर की राशि शून्य है तो उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के तहत देय विलंब फीस को उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए अधित्यजन किया जाता है जिन्होंने नियत तारीख तक माह जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है लेकिन वह उक्त विवरणी को 1 जुलाई, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 की अवधि के दौरान प्रस्तुत करते हैं।”।

[फा.सं. सीबीईसी- 20/06/09/2019- जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट : मूल अधिसूचना सं. 76/2018- केन्द्रीय कर दिनांक 31 दिसम्बर 2018 को सा.का.नि. 1253 (अ), दिनांक 31 दिसम्बर, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधन अधिसूचना सं. 32/2020- केन्द्रीय कर दिनांक 3 अप्रैल, 2020 के द्वारा किया गया था जिस को सा.का.नि. 232 (अ), दिनांक 3 अप्रैल, 2020, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2020

No. 52/2020—Central Tax

G.S.R. 405(E).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 76/2018— Central Tax, dated the 31st December, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i) vide number G.S.R. 1253(E), dated the 31st December, 2018, namely :—

In the said notification,-

(i) in the third proviso, for the Table, the following Table shall be substituted, namely : —

“TABLE

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Tax period (3)	Condition (4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	February, 2020, March, 2020 and April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 24 th day of June, 2020
2.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana or Andhra Pradesh or the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep	February, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30 th day of June, 2020
		March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 3 rd day of July, 2020
		April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 6 th day of July, 2020
		May, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 12 th day of September, 2020
		June, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 23 rd day of September, 2020
		July, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 27 th day of September, 2020
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the States of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha or the Union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh and Delhi	February, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 30 th day of June, 2020
		March, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 5 th day of July, 2020
		April, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 9 th day of July, 2020
		May, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 15 th day of September, 2020
		June, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 25 th day of September, 2020

		July, 2020	If return in FORM GSTR-3B is furnished on or before the 29 th day of September, 2020
--	--	------------	--

(ii) after the third proviso, the following provisos shall be inserted, namely: –

“Provided also that the total amount of late fee payable for a tax period, under section 47 of the said Act shall stand waived which is in excess of an amount of two hundred and fifty rupees for the registered person who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of July, 2017 to January, 2020, by the due date but furnishes the said return between the period from 01st day of July, 2020 to 30th day of September, 2020:

Provided also that where the total amount of central tax payable in the said return is nil, the total amount of late fee payable for a tax period, under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered person who failed to furnish the return in **FORM GSTR-3B** for the months of July, 2017 to January, 2020, by the due date but furnishes the said return between the period from 01st day of July, 2020 to 30th day of September, 2020.”.

[F. No. CBEC-20/06/09/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification No. 76/2018-Central Tax, dated 31st December, 2018 was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 1253(E), dated the 31st December, 2018 and was last amended *vide* notification number 32/2020 – Central Tax, dated the 3rd April, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.232 (E), dated the 3rd April, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

सं 53/2020- केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 406(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की शिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 04/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 53 (अ), दिनांक 23 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिसूचना के तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के तहत देय विलंब फीस की राशि को उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में उल्लिखित महीनों या तिमाही के लिए जावक प्रदाय की विवरणी प्ररूप जीएसटीआर-1 में नियत तारीख तक प्रस्तुत नहीं करते हैं, लेकिन उक्त विवरणी को उक्त तालिका के स्तंभ (3) में उल्लिखित तारीख या उससे पहले प्रस्तुत करते हैं, अधित्यक्त करती है :

तालिका

क्र.सं. (1)	माह/ तिमाही (2)	तारीख (3)
1	मार्च 2020	जुलाई, 2020 का 10वां दिन
2	अप्रैल, 2020	जुलाई, 2020 का 24वां दिन
3	मई, 2020	जुलाई, 2020 का 28वां दिन
4	जून, 2020	अगस्त, 2020 का 5 वां दिन

5	जनवरी से मार्च, 2020	जुलाई, 2020 का 17वां दिन
6	अप्रैल से जून, 2020	अगस्त, 2020 का 3 वां दिन।

[फा.सं. सीबीईसी- 20/06/09/2019- जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट : मूल अधिसूचना सं. 4/2018- केन्द्रीय कर, दिनांक 23 जनवरी, 2018, जो सा.का.नि. 53 (अ), दिनांक 23 जनवरी 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और आखिरी बार इसे संशोधित अधिसूचना सं. 33/2020 – केन्द्रीय कर, दिनांक 3 अप्रैल, 2020, जो सा.का.नि. 233 (अ) दिनांक 3 अप्रैल, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2020

No. 53/2020 – Central Tax

G.S.R. 406(E).— In exercise of the powers conferred by section 128 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 4/2018–Central Tax, dated the 23rd January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i) *vide* number G.S.R. 53(E), dated the 23rd January, 2018, namely:—

In the said notification, for the third proviso, the following proviso shall be substituted, namely: –

“Provided also that the amount of late fee payable under section 47 of the said Act shall stand waived for the registered persons who fail to furnish the details of outward supplies for the months or quarter mentioned in column (2) of the Table below in **FORM GSTR-1** by the due date, but furnishes the said details on or before the dates mentioned in column (3) of the said Table:—

TABLE

Sl. No. (1)	Month/ Quarter (2)	Dates (3)
1.	March, 2020	10 th day of July, 2020
2.	April, 2020	24 th day of July, 2020
3.	May, 2020	28 th day of July, 2020
4.	June, 2020	05 th day of August, 2020
5.	January to March, 2020	17 th day of July, 2020
6.	April to June, 2020	03 rd day of August, 2020.”.

[F. No. CBEC-20/06/09/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification No. 4/2018– Central Tax, dated the 23rd January, 2018, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (i) *vide* number G.S.R. 53(E), dated the 23rd January, 2018 and was last amended by notification No. 33/2020- Central Tax, dated the 3rd April, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 233(E) dated the 3rd April, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

सं 54/2020- केन्द्रीय कर

सा.का.नि. 407(अ).— आयुक्त, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् इस अधिसूचना में उक्त नियम कहा गया है) के नियम 61 के उपनियम (5) के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, भारत सरकार,

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 29/2020-केंद्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 212 (अ), तारीख 23 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना के, पहले पैरा में, पांचवां परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुकों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह भी कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रूपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, गोवा राज्य, केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य, तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र, पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में है, अगस्त, 2020 के मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, 1 अक्टूबर, 2020 को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी :

परंतु यह भी कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त पांच करोड़ रूपए तक का होने वाले करदाताओं के लिए, जिनका कारबार का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश राज्य, पंजाब राज्य, उत्तराखंड राज्य, हरियाणा राज्य, राजस्थान राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, सिक्किम राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य, नागालैंड राज्य, मणिपुर राज्य, मिजोरम राज्य, त्रिपुरा राज्य, मेघालय राज्य, असम राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, झारखंड राज्य या ओडिशा राज्य, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में है, अगस्त, 2020 के मास के लिए विवरणी उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआर-3ख में सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, 3 अक्टूबर, 2020 को या उसके पूर्व प्रस्तुत की जाएगी।”।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/09/2019-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 29/2020-केंद्रीय कर, तारीख 23 मार्च, 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. 212(अ), तारीख 23 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसका आखिरी बार संशोधन अधिसूचना सं. 36/2020- केन्द्रीय कर दिनांक 3 अप्रैल, 2020 के द्वारा किया गया था जिस को सा.का.नि. 236 (अ), दिनांक 3 अप्रैल, 2020, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2020

No. 54/2020 – Central Tax

G.S.R. 407(E).—In exercise of the powers conferred by section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), read with sub-rule (5) of rule 61 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said Rules), the Commissioner, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 29/2020 – Central Tax, dated the 23rd March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 212 (E), dated the 23rd March, 2020, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, after the fifth proviso, the following provisos shall be inserted, namely: –

“Provided also that, for taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Andhra Pradesh, the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep, the

return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the month of August, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 1st day of October, 2020:

Provided also that, for taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees five crore rupees in the previous financial year, whose principal place of business is in the States of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha, the Union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh or Delhi, the return in **FORM GSTR-3B** of the said rules for the month of August, 2020 shall be furnished electronically through the common portal, on or before the 3rd day of October, 2020.”.

[F. No. CBEC-20/06/09/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification number 29/2020 – Central Tax, dated the 23rd March, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.212(E), dated the 23rd March, 2020 and was last amended vide notification number 36/2020 – Central Tax, dated the 3rd April, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.236(E), dated the 3rd April, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

सं 02/2020- संघ राज्यक्षेत्र कर

सा.का.नि. 408(अ).—सरकार, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं०10/2017- केन्द्रीय कर, दिनांक 30 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 747(अ), दिनांक 30 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं, देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं:-

तालिका

क्र.सं. (1)	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	ब्याज की दर (3)	कर अवधि (4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद 24 जून, 2020 तक 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो और जिनका कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, गोवा	30 जून, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30	फरवरी, 2020

	राज्य, केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य, तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र, पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में है	सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	
		3 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	मार्च, 2020
		6 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	अप्रैल, 2020
		12 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	मई, 2020
		23 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	जून, 2020
		27 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	जुलाई, 2020
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो और जिनका कारबार का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश राज्य, पंजाब राज्य, उत्तराखंड राज्य, हरियाणा राज्य, राजस्थान राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, बिहार राज्य, सिक्किम राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य, नागालैंड राज्य, मणिपुर राज्य, मिजोरम राज्य, त्रिपुरा राज्य, मेघालय राज्य, असम राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, झारखंड राज्य या ओडिशा राज्य, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में है	30 जून, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020
		5 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	मार्च, 2020
		9 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और	अप्रैल, 2020

		उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	
		15 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	मई, 2020
		25 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	जून, 2020
		29 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	जुलाई, 2020 ¹ ।

[फा.सं.-सीबीईसी-20/06/09/2019-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट: मूल अधिसूचना सं. 10/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 747 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और पश्चातवर्ती अधिसूचना सं. 01/2020- संघ राज्यक्षेत्र कर, तारीख 8 अप्रैल, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 243(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अंतिम संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2020

No. 02/2020—Union Territory Tax

G.S.R. 408(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), read with sub-section (1) of section 50 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 10/2017 – Union Territory Tax, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 747(E), dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that the rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table given below for the period mentioned therein, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in **FORM GSTR-3B**, but fail to furnish the said return along with payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due date, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Rate of interest (3)	Tax period (4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	Nil for first 15 days from the due date, and 9 per cent thereafter till 24 th day of June, 2020	February, 2020, March 2020, April, 2020
2.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana or Andhra Pradesh or the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep	Nil till the 30 th day of June, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	February, 2020
		Nil till the 3 rd day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	March, 2020
		Nil till the 6 th day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	April, 2020
		Nil till the 12 th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	May, 2020
		Nil till the 23 rd day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	June, 2020
		Nil till the 27 th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	July, 2020
		3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the States of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha or the Union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh and Delhi
Nil till the 5 th day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	March, 2020		
Nil till the 9 th day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	April, 2020		
Nil till the 15 th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	May, 2020		
Nil till the 25 th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of	June, 2020		

		September, 2020	
		Nil till the 29 th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30 th day of September, 2020	July, 2020.”.

[F. No. CBEC-20/06/09/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification number 10/2017 – Union Territory Tax, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.747(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended vide notification number 01/2020 – Union Territory Tax, dated the 8th April, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 243(E), dated the 8th April, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

संख्या. 04/2020-एकीकृत कर

सा.का.नि. 409(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम 2020 (2020 का 12) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 30 जून, 2020 को उस तारीख के रूप में, जिससे उक्त अधिनियम की धारा 134 के उपबंध प्रवृत्त होंगे, नियत करती है।

[फा.सं. सीबीईसी- 20/06/09/2019- जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2020

No. 04/2020 – Integrated Tax

G.S.R. 409(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Finance Act, 2020 (12 of 2020) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby appoints the 30th day of June, 2020, as the date on which the provisions of section 134 of the said Act, shall come into force.

[F. No. CBEC- 20/06/09/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2020

सं 05/2020- एकीकृत कर

सा.का.नि. 410(अ).—सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 06/2017- एकीकृत कर, दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 698(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् –

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं, देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं:-

तालिका

क्र०सं० (1)	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	ब्याज की दर (3)	कर अवधि (4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद जून 24, 2020 तक 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो और जिनका कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, गुजरात राज्य, महाराष्ट्र राज्य, कर्नाटक राज्य, गोवा राज्य, केरल राज्य, तमिलनाडु राज्य, तेलंगाना राज्य, आंध्र प्रदेश राज्य, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र, पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में है	30 जून, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020
		3 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	मार्च, 2020
		6 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	अप्रैल, 2020
		12 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	मई, 2020
		23 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	जून, 2020
		27 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत,	जुलाई, 2020

		और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो और जिनका कारबार का मुख्य स्थान हिमाचल प्रदेश राज्य ,पंजाब राज्य ,उत्तराखंड राज्य ,हरियाणा राज्य , राजस्थान राज्य ,उत्तर प्रदेश राज्य ,बिहार राज्य ,सिक्किम राज्य , अरुणाचल प्रदेश राज्य ,नागालैंड राज्य ,मणिपुर राज्य , मिजोरम राज्य ,त्रिपुरा राज्य ,मेघालय राज्य ,असम राज्य , पश्चिम बंगाल राज्य ,झारखंड राज्य या ओडिशा राज्य ,जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र ,लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र ,चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में है	30 जून, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020
		5 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	मार्च, 2020
		9 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	अप्रैल, 2020
		15 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	मई, 2020
		25 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	जून, 2020
		29 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर, 2020 तक 9 प्रतिशत	जुलाई, 2020।"।

[फा.सं.-सीबीईसी-20/06/09/2019-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

नोट: मूल अधिसूचना सं. 06/2017-एकीकृत कर, दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 698 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और पश्चातवर्ती अधिसूचना सं. 03/2020- एकीकृत कर, तारीख 8 अप्रैल, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 242(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अंतिम संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2020

No. 05/2020 – Integrated Tax

G.S.R. 410(E).— In exercise of the powers conferred by section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), read with sub-section (1) of section 50 and section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 6/2017 – Integrated Tax, dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 698(E), dated the 28th June, 2017, namely:—

In the said notification, in the first paragraph, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that the rate of interest per annum shall be as specified in column (3) of the Table given below for the period mentioned therein, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who are required to furnish the returns in **FORM GSTR-3B**, but fail to furnish the said return along with payment of tax for the months mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table by the due date, namely:—

TABLE

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Rate of interest (3)	Tax period (4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	Nil for first 15 days from the due date, and 9 per cent thereafter till 24th day of June, 2020	February, 2020, March 2020, April, 2020
2.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the States of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Goa, Kerala, Tamil Nadu, Telangana or Andhra Pradesh or the Union territories of Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli, Puducherry, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep	Nil till the 30th day of June, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	February, 2020
		Nil till the 3rd day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	March, 2020
		Nil till the 6th day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	April, 2020
		Nil till the 12th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	May, 2020
		Nil till the 23rd day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	June, 2020
		Nil till the 27th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	July, 2020
		Nil till the 30th day of June, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	February, 2020
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year, whose principal place of business is in the States of Himachal Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Haryana, Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram,	Nil till the 30th day of June, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	February, 2020

Tripura, Meghalaya, Assam, West Bengal, Jharkhand or Odisha or the Union territories of Jammu and Kashmir, Ladakh, Chandigarh and Delhi	Nil till the 5th day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	March, 2020
	Nil till the 9th day of July, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	April, 2020
	Nil till the 15th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	May, 2020
	Nil till the 25th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	June, 2020
	Nil till the 29th day of September, 2020, and 9 per cent thereafter till the 30th day of September, 2020	July, 2020.?"

[F. No. CBEC-20/06/09/2019-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note: The principal notification number 06/2017 – Integrated Tax, dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R.698(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended *vide* notification number 03/2020 – Integrated Tax, dated the 8th April, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 242(E), dated the 8th April, 2020.